RAJYA SABHA

Thursday, the 12th September, 1991/ 21 Bhadra, 1913 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Question No. 241. (*Interruptions*)

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Sir, granite mines worth Rs. 3,500 crores have been looted in Andhra Pradesh. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Question Hour will begin. Nothing else will go on record.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: *

MR. CHAIRMAN: We have to carry on with the Business according to the rules. It is Question Hour. Except questions, nothing else will go on record.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: *

MR. CHAIRMAN: Dr. Reddy, you are wasting your breath. Nothing will go on record. If I may use a strong term, you are wasting the time of the House.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY:*

SHRI SUKOMAL SEN:*

MR. CHAIRMAN: It is a very serious thing that senior Members like Dr. Reddy and Mr. Sukomal Sen are doing it, are behaving like this. Please sit down. If you want the rules to be suspended, it is a different matter. Otherwise, Question Hour will begin. Shri Ajit P. K. Jogi.

सौ करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली केन्द्रीय परियोजनाओं में हुई प्रगति

*241. श्री अजीत जोगी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक सौ करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली ऐसी केन्द्रीय परियोजनाओं के संबंध में किये गये ताजा सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है जिनके निर्माण-कार्य में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति नहीं हो रही है ;

(ख) इन परियोजनाओं की लागत में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग) सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) 1 अगस्त, 1991 की स्थिति के अनुसार, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबोधन प्रणाली में प्रत्येक 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली 116 केन्द्रीय परियोजनाओं में से, नवीनतम अनुमोदित निर्धारित समय के संदर्भ में, 7 परियोजनाएं निर्धारित समय से आगे थीं, 49 परियोजनाएं निर्धारित समय पर थीं तथा 60 परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे थीं । प्रत्येक विलम्बित परियोजना लागत वृद्धि संलग्न अनुबंध में दी गई है ।

(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबोधन कर रहा है और परियोजनाओं को निर्धारित समय में शीघ्र पूरा करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उचित सामयिक कार्रवाई करने के लिए समस्या-ग्रस्त क्षेत्रों पर प्रकाश डाल रहा है ।

*Not recorded.

अनुबन्ध

1 अगस्त, 1991 को स्थिति के अनुसार अनुमोदित निर्धारित समय के संदर्भ में प्रत्येक 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली विलम्बित केन्द्रीय परियोजनाओं की लागत वृद्धि संबंधी ब्योरा

क्रम सं0	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रुपये)		लागत वृद्धि (करोड़ रु०)
		नवीनतम स्वीकृत	नवीनतम प्रत्याशित	
परमाणु ऊर्जा				
1	नरोरा परमाणु विद्युत-1 और 2 (एन0पी0सी0)	399.64	745.00	345.36
2	ककरापार परमाणु विद्युत-1 और 2 (एन0पी0सी0)	745.00	1078.00	333.00
3	भारी जल परियोजना, मनुगुरू (डी0ए0ई0)	647.28	647.28	0.00
कोयला				
4	पुटकी बलिहारी (बी0सी0सी0एल0)	199.87	365.96	166.09
5	झरिया खंड-2 (टी0सी0सी0एल0)	112.05	173.82	61.77
6	झंझरा यू0जी0 (ई0सी0एल0)	184.55	573.89	389.34
7	सोनर-बजारी "ए" ओ0सी0 (ई0सी0एल0)	192.96	453.00	260.04
8	इम्लोहरी (एन0सी0एल0)	527.11	527.11	0.00
9	बीना (एन0सी0एल0)	168.64	168.64	0.00
10	कांकरी (एन0सी0एल0)	137.80	137.80	0.00
11	400 के0वी0ए0 संचरण प्रणाली स्तर-2 (एन0एल0सी0)	367.74	367.74	0.00
12	नेवेली द्वितीव खान विस्तार (एन0एल0सी0)	1065.40	1065.40	0.00
13	मनुगुरु ओ0सी0-2 (सिंगरेनी कोलरिज)	132.00	199.94	67.94
14	रामागुंडम-2 ओ0सी0 (सिंगरेनी कोलरिज)	147.16	512.02	364.86
15	गोदावरी खानी II-ए (एस0सी0सी0एल0)	156.00	156.00	0.00
उर्वरक				
16	हल्दिया उर्वरक परियोजना (ए0एफ0सी0)	281.96	624.00	342.04
खान				
17	रामपुरा अगुचा-चेन्देरियन लिड जिंक कांप्लेक्स (एच0जैड0एल0)	617.20	705.42	88.22

क्रम सं०	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रुपये)		लागत वृद्धि (करोड़ रु०)
		नवीनतम स्वीकृत	नवीनतम प्रत्याशित	
	इस्पात और लोह अयस्क			
18	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आधुनिकीकरण (सेल) .	2667.60	3121.28	453.68
19	राऊरकेला इस्पात संयंत्र आधुनिकीकरण (सेल)	2461.00	2461.00	0.00
20	विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना (आर०आई० एन०एल०)	6849.70	8130.28	1280.58
	रसायन तथा पेट्रो रसायन			
21	महाराष्ट्र गैस क्रेकर परिसर (आई०पी०सी० एल०)	1390.00	1390.00	0.00
	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस			
22	गैस स्वीटनिंग संयंत्र चरण-2 (ओ०एन० जी०सी०) . . .	204.65	260.27	55.62
23	गंधार विकास चरण-I (ओ०एन०जी०सी०)	326.68	257.93	-68.75
24	गैसलिफ्ट स्कीम (ओ०एन०जी०सी०) .	561.30	392.59	-168.71
25	अतिरिक्त गौण प्रक्रिया सुविधा गुजरात रिफाइनरी (आई०ओ०सी०) . .	635.00	757.24	122.24
26	बम्बई रिफाइनरी-लूबे आधारित स्टाक वृद्धि (एच०पी०सी०एल०) . . .	181.23	181.23	0.00
	विद्युत			
27	फरक्का एस०टी०पी०पी० स्तर-2 (एन०टी० पी०सी०)	868.48	1331.31	462.83
28	फरक्का संचरण लाइन स्तर-2 (एन०टी० पी०सी०)	134.91	199.06	64.15
29	रिहंद संचरण लाइन (एन०टी०पी०सी०)	1063.00	1063.00	0.00
30	विंध्याचल एस०टी०पी०पी०-2 अग्रीम कार्रवाई (एन०टी०पी०सी०) . .	103.50	103.50	0.00
31	कहल गांव एस०टी०पी०पी० स्तर-I (एन०टी० पी०सी०)	884.15	1552.38	668.23
32	कहलगांव संचरण लाइन स्तर-1 (एन०टी० पी०सी०	174.48	217.45	42.97

क्रम सं०	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रुपये)		लागत वृद्धि (करोड़ रु०)
		नवीनतम स्वीकृत	नवीनतम प्रत्याशित	
33	केन्द्रीय संचरण परियोजना (एन०टी०पी०सी०)	388.05	453.00	64.95
34	कवास गैस विद्युत परियोजना (एन०टी०पी०सी०)	373.98	877.25	503.27
35	औरेया जी0पी0पी0 संचरण लाइन (एन०टी०पी०सी०)	100.61	110.66	10.05
36	बोकारो बी-2 तापीय विद्युत परियोजना (डी०वी०सी०)	186.93	356.25	169.32
37	मेजिया तापीय विद्युत परियोजना (डी०वी०सी०)	566.00	1134.00	568.00
38	कोयल कारो हाइड्रो विद्युत परियोजना (एन०एच०पी०सी०)	439.91	1338.80	898.89
39	धुलहस्ती संचरण लाइन (एन०एच०पी०सी०)	166.57	772.83	606.26
40	चमेरा हाइड्रो इलैक्ट्रोक परियोजना (एन० एच०पी०सी०)	809.29	1725.50	916.21
41	टनकपुर हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (एन० एच०पी०सी०)	178.75	376.76	198.01
42	रंगीत एच०ई०पी०-3 (एन०एच०पी०सी०)	181.15	181.15	0.00
43	नाथवा झाकरी संचरण प्रणाली (एन०एच० पी०सी०)	889.95	889.95	0.00
44	दोरांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (निप्को)	128.61	251.01	122.40
45	रंग नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, स्तर-I (निप्को)	312.78	516.49	203.71
46	कैथलगुड़ी गैस आधारित संयुक्त साइकिल पावर परियोजना (निप्को)	203.17	989.03	785.86
47	कैथलगुड़ी जी०बी०सी०सी०पी०पी० संचरण लाइन (निप्को)	301.38	565.41	264.03
48	नाथपा झाकरी एच०ई०पी० (एन०जे०पी०सी०)	1678.02	2140.00	461.98
	कागज, सीमेंट तथा आटो			
49	बगास आधारित न्यूजप्रिंट (नेपा)	414.46	414.46	0.00
50	येरागुटला सीमेंट परियोजना (सी०सी०आई०)	191.25	240.68	49.43

क्रम सं०	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रुपये)		लागत वृद्धि (करोड़ रु०)
		नवीनतम स्वीकृत	नवीनतम प्रत्याशित	
	रेलवे			
51.	मालखेड़-बेलापुर रेलवे लाइन विस्तार, एम० टी-पी०	153.03	287.11	134.08
52.	जोगीगोपा-गोहार्ट नई लाइन	238.93	444.22	205.29
53.	गूना-इटावा नई लाइन	248.00	253.08	5.08
54.	न्यू बोंजो लाइन, कोरापुट-रायगढ़ द० पू० रे०	322.00	322.00	0.00
55.	डीजल कम्पोनेंट वर्क्स (डी०सी०डब्ल्यू० पटियाला)	133.84	235.78	101.94
56	नागपुर-दुर्ग रेलवे विद्युतीकरण	74.38	124.88	50.50
57	सोलापुर-पतरातू विद्युतीकरण	110.50	112.45	1.95
	भू-तल परिवहन			
58.	अधिग्रहण-3 एल०आर०-2 प्रत्येक 85200 डी०डब्ल्यू०टी० का ट्रक (एस०सी०आई०/ सी०ए०ए०एल०)	138.12	154.41	16.29
59.	अहमदाबाद-बड़ोदा एक्सप्रेस वे (गुजरात सरकार)	137.20	207.00	69.80
60.	न्हावा शेवा पत्तन परियोजना (एन०एस० पी टी०)	986.08	1056.00	69.

श्री अजीत जोगी: सभापति महोदय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि सौ करोड़ से अधिक की 116 योजनाओं में से 60 योजनाएं निर्धारित समय से पीछे हैं। ये जो 60 योजनाएं समय पर पूरी नहीं हुई हैं, उनके विषय में मंत्री जी ने कास्ट और टाइम ओवर-रन बताया है वह आयाम में बहुत ही बड़ा है। इन 60 योजनाओं में लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का कास्ट ओवर-रन हुआ है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि चूंकि उन्होंने अपने उत्तर में यह बताया है कि कास्ट ओवर-रन है इन बड़ी योजनाओं पर तो वे यह भी बताएं कि वे कौनसे प्रमुख कारण हैं जिनसे इन बड़ी योजनाओं पर इतना अधिक पैसा केवल इसलिए बढ़ गया है क्योंकि उनको समय पर पूरा नहीं किया जा सका। तो ऐसे कौन से मोटे मोटे कारण हैं उन्हें बताएं।

इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जब इनकी मॉनिटरिंग मंत्रालयों द्वारा की जाती है तो क्या किसी को उन्होंने इन योजनाओं के कास्ट और टाइम ओवर रन के लिए उत्तरदायी पाया है। यदि समय पर योजनाएं पूरी होती हैं तो क्या उसके लिए कोई इंसेंटिव है? यदि

समय पर योजनाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसके लिए दंड है ? तो दंड या प्रलोभन की कोई योजना है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि यदि मुख्य कारण इन योजनाओं के कास्ट और टाइम ओवर रन का यह है कि इनको समय पर पूरा आबंटन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं ? तो क्या प्राथमिकताएं तय की जाएंगी उन योजनाओं को छांट लिया जाएगा और उनको आबंटन देकर उनको समय पर पूरा कराने की कोशिश की जाएगी ?

SHRI H. R. BHARDWAJ: Mr. Chairman, Sir, I seek your permission to answer this question in English.

Major causes which cause cost escalation are:

(1) Delay in acquisition of land. (2) Delay in obtaining clearance from forest|environmental angle and lack of advance action for development of infrastructure. (3) Inadequate project preparation. (4) Delay in tie-up of adequate funds and sources of funds (budgetary,, internal, extra-budgetary and external). (5) Delay in finalisation of detailed engineering. (6) Frequent scope changes. (7) Delay in tendering and ordering. (8) Lack of delineation of responsibility with the consultant and the project organisation. (9) Industrial relation and law and order problems. (10) Inadequate supply of inputs. (11) Non-sequential and delayed supply of fabricated equipment. (12) Teething troubles due to mal-functioning of equipment. (13) Selection of unproven technology. (14) Delays in right of use (ROU) clearances. (15) Difficult geology of project sites.

These are a few major causes which make the cost escalation. With regard to incentive and disincentive, this Department of Project Implementation was started in 1985. After that a few decisions were taken by the Government that we should try to bring accountability also in the system. So, it was decided that when we put the chief executive of the project, he should be given sufficient time so that his tenure lasts up to the completion of the project and accountability was also one of the factors that was highlighted. This has shown results during the past few years, but we are still not satisfied with it. We are now finding out other methods with a view to stop this type of escalation in cost and delays in implementation of projects. Perhaps some more drastic steps will be needed. We will take up this matter at the appropriate level.

So far as our Department of Programme implemention is concerned, we point out all these things to the nodal Ministries, to the administrative Ministries of Power, Coal and other Departments, wherever the projects are located. Sometimes delays occur in the States also in land acquisition, for example. So, a very well coordinated effort will have to be there because we cannot tolerate wastage of public funds. With regard to encouraging the leaders and the workers who work on the project, they are completing the project; that is a part of the public duty and the Government will encourage such executives and workers.

SHRI AJIT P. K. JOGI: Have they ever been punished? That is what I have asked.

SHRI H. R. BHARDWAJ I am aware that in quite a few cases enquiries have been ordered. But I don't have the details now. I will get them for him. In a few cases it is my knowledge that we have asked for accountability. If at all any punishment is to be given, that has to be dealt with by the administrative Ministries.

श्री अजीत जोगी : : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया है कि उनके मंत्रालय द्वारा इन बड़ी परियोजनाओं की मोनिटरिंग की जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मोनिटरिंग का मैकेनिज्म क्या है ? क्या वह मोनिटरिंग केवल अधिकारियों के स्तर पर होती है

या मंत्री महोदय के स्तर पर होती है ? उनकी ये परियोजनाएं विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध हैं तो क्या मोनिटरिंग जब की जाती है उस समय विभिन्न सम्बन्धित विभागों के मंत्रियों के साथ बैठकर, कम से कम ये जो बड़ी परियोजनाएँ हैं 100 करोड़ से ऊपर की, उनके ऊपर चर्चा होती है या सम्बन्धित अधिकारियों तक ही सीमित रहती है ? इस उत्तर में दिया गया है कि इसमें मुख्यतः तीन ऐसे विभाग हैं जिनकी परियोजनाएं बहुत अधिक संख्या में कास्ट, टाइम ओवररन से प्रभावित हैं यानी पावर, रेलवे और कोल । इन तीनों सेक्टर्स के लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था है मोनिटरिंग की ? क्या मंत्री महोदय के स्तर पर मोनिटरिंग इन परियोजनाओं के संबंध में की जा रही है ?

SHRI H. R. BHARDWAJ: Sir, the hon. Member will appreciate that all these projects are under the administrative charge of various Ministries. The Department of Programme Implementation interacts with the chief of the project and, wherever it is needed with the State Government and also at the official level. We get monthly and quarterly reports from the project also. We have a computerised network in the Programme Implementation Ministry where monthly and quarterly and yearly reviews are received directly from the project site. After that we discuss them at the Secretaries level. I also personally write to the Minister and the Chief Minister highlighting what is to be done in the particular project. I have been able to review only Energy, that is, the NTPC, very recently. I took all the officials and the managers concerned into confidence. I found that they have built a mechanism in the projects and in the organisation itself. That has benefited a lot. So, after 1985 till today a lot of effort has been made. But I still maintain that we want to strengthen it to the maximum possible extent. I am going to take this matter up with the Ministers as well as with the Government also.

SHRI AJIT P. K. JOGI: Don't you feel that action should be with the Minister concerned who will deal with it better?

SHRI H. R. BHARDWAJ: Sir, this is definitely there.. We know ...

श्री सभापति : जवाब हो गया। तीसरा सवाल थोड़े ही पूछा जाता है ।

श्री रामदास अग्रवाल : सभापति जी, मंत्री महोदय ने सरकारी उपक्रमों में जो प्रोजेक्टस लगा रहे हैं उनमें जो देरी होती है उनके इम्पलीमेंटेशन में, उसका विवरण दिया । एक बात ध्यान में आनी चाहिए हमारे सदन के और मंत्री महोदय के भी कि पब्लिक सेक्टर फेल होते हैं जहां नफा कमाने का सवाल होता है, प्रोफिट कमाने का सवाल होता है । गये तीन साल में उन्होंने 5 हजार करोड़ रुपये का लॉस किया । पब्लिक सेक्टर में किसी प्रोजेक्ट के इम्पलीमेंटेशन का सवाल है उसमें मंत्री महोदय ने कहा कि जमीन लेने में, पावर लेने में इत्यादि कामों में प्रोजेक्ट डिले होते हैं । ये कई स्टेजेज होती हैं डिले होने की । एक स्टेज हो सकती है जमीन लेने के बारे में या पावर लेने के बारे में, उसका निर्णय भी सरकार को करना होता है । और सरकार का ही उपक्रम होता है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आखिर हम लोग जो पब्लिक इंटरेस्ट को देखना चाहते हैं और 30 हजार करोड़ रुपयों से अधिक का खर्चा इम्प्लिमेंटेशन में डिले के कारण हो चुका है, इसके लिए हम कोई ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं डेवलप कर लेते हैं जिससे देरी न हो ? पिछले कई वर्षों से हम यह बात सुनते आ रहे हैं कि हम इसके बारे में जांच करेंगे, इसकी रिस्पोंसबिलिटी फिक्स करेंगे । इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आखिर हम हजारों-लाखों करोड़ों रुपयों का इंवेस्टमेंट करते हैं, उसमें हम एक मैकेनिज्म क्यों नहीं डेवलप कर लेते हैं जिसके माध्यम से जो इसके लिए उत्तरदायी है उनको सीधे सीधे सब प्रकार के कानून के तहत दण्ड दिया जा सके ? जब तक यह व्यवस्था नहीं होगी तब तक सरकारी रुपया इसी प्रकार से नुकसान में बहता जाएगा, इसी प्रकार से प्रोजेक्ट

की इम्प्लीमेंटेशन में डिले होती रहेगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर पब्लिक प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन में देरी न होने देने के लिए कब तक आप इस प्रकार का मैकेनिजम फाइनल करके सदन को सूचित कर सकेंगे ?

श्री हंसराज भारद्वाज : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि किन किन कारणों से डिले होती है। वह मैं बता चुका हूं।

श्री सभापति : वे यह कह रहे हैं कि मैकेनिजम ऐसा निकालिए कि जिससे देरी न हो और हो तो फौरन पता लग जाय। वह आप कब तक करेंगे, यह वे पूछ रहे हैं।

श्री हंसराज भारद्वाज : वह मैकेनिजम तो अभी है, लेकिन जैसे जमीन एक्वायर करने में जो समय लगता है..... **(व्यवधान)**।

श्री रामदास अग्रवाल : आप अभी तक किसी को सजा तो दे नहीं पाये हैं।

श्री हंसराज भारद्वाज : आप सुनेंगे तो तभी बात समझ में आएगी। जो जमीन एक्वायर करते हैं वह तो राज्य सरकारें करती हैं। बहुत सारी ऐसी योजनायें हैं, अगर आप लिस्ट चाहें, तो मैं दे सकता हूं, जिस जमीन पर प्रोजेक्ट लगनी है वह एक्वायर नहीं हुई, किसान वहां पर कब्जा दे नहीं रहे हैं। हम राज्य सरकारों के साथ लगातार सम्पर्क बनाये हुए हैं कि ह जमीन ले लो। सालों इसमें जमीन लेने में लग जाते हैं। यह राज्य सरकारों की प्रोबल्म है, उनको हम दण्ड कैसे दे सकते हैं ? उसके बाद एस्केलेशन टैक्स की वजह से हो जाता है, इसमें कस्टम भी आ जाता है। फोरेन कम्पोनेन्ट्स में जो एस्केलेशन हो जाता है, तो वह भी इसमें आ जाता है।

SHRI E. BALANANDAN: There is no remedy for this.

SHRI H. R. BHARDWAJ: If you listen, then, I will tell you. This is the difficulty. If you want to discuss a problem ...

MR. CHAIRMAN: You put your point. Sometime land is not acquired. Advocates like him come in the way.

SHRI H. R. BHARDWAJ: We can punish those defaulting officers or workers at the site. You can fight with the State Government. There is a mechanism to locate the default. At the initial stages the cost is underestimated. That is where we want to work. We have already taken up this matter. The under-estimation of cost at the initial stages of the project is one of the reasons; we are thinking to remedy it.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the Minister of Programme Implementation, if he has information about the present change of circumstances and atmosphere in the country due to heavy shortage of resources. Therefore, how does the Government plan to implement the half-way-through projects? Will they be delayed or they will be associated with the private sector, particularly item No. 17 of the reply to the question, Rampura Agucha-Chanderiyan Lead Zinc complex? The cost escalation of this project is Rs. 88.22 crores only. I hope this project will now be implemented in time. I I would like to have the information from the Minister.

SHRI H. R. BHARDWAJ: This is not within the ambit of the question.

MR. CHAIRMAN: He wants to know why this particular project has been delayed. Kindly see to it.

SHRI H. R. BHARDWAJ: I will have to talk to the administrative Ministry and then I will send him the answer.

SHRI K. G. MAHESHWARAPPA: Mr. Chairman, Sir, even in regard to the case where environmental clearance has been given and where courts have passed stay orders, no action has been taken by the Environment Ministry to accord approval to the projects. I will give you one instance. Sharavati Tail-end hydroelectric project involving Rs. 700 crores of forest land in Karnataka was cleared under the Forest Clearance Act a long time back. The The High Court has issued a stay order and directed the Central Government to reconsider the issue on environment... forest clearance and submit a report within three months. Now it is already ten months. But the report has not been submitted. The Government of Karnataka has already committed Rs. 100 crores and spent Rs. 21 crores. It is a World Bank-aided project. The work has been stopped and escalation of cost is there. For all these ten months, the Ministry has been sleeping. I want to know from the Minister whether he is aware of the instance. Even with regard to the Kaiga Atomic Power Plant Project, there is a movement and the Government has not taken it seriously. We are surprised to see that the Ministry of Environment sometimes acts quickly and sometimes delays matters. The former Minister for Environment was keeping even small formal clearance matters pending clearance. I want to know from the Minister whether he will see that on-going projects are not delayed so that cost escalation may be avoided.

SHRI H. R. BHARDWAJ: Sir, I am grateful to the hon. Member ... He has agreed that it is one of the reasons why projects are delayed. I will take it up with the Environment Minister so that a quick decision may be taken. We will also take the necessary follow-up action. This particular project is noted. I am also aware of this. I will take it up myself because I value the suggestion of the hon. Member and I am grateful to him.

SHRI JAGESH DESAI: Mr. Chairman, Sir, the reply given does not give a clear picture of the escalation. The figures here are given on the basis of the revised sanction. I would like to know what the original sanction was of these projects because, here what you have done is, you have given the latest revised estimates. According to my information, the total escalation at present is Rs. 30,000 crores in respect of the projects which are already sanctioned and which are under construction. One main reason is, deliberately, at the time when the project report is prepared, some of the major items are left out and the cost is shown as less so that the Public Investment Board can clear it and the Cabinet Committee may also clear it. I understand—and I have my own experience—that deliberately it is kept low. That is why there is escalation later. Also, after the devaluation, the costs of import contents have increased. I would like to know whether that aspect has also been taken into consideration when you have given the revised sanction figures so that a clear picture can emerge.

SHRI H. R. BHARDWAJ: The impact of the adjustment of exchange rate has not yet been assessed. But I could see the point of the hon. Member when he says that at the time of the beginning or at the formulation stage of a project, a proper estimate is not presented to the PIB. We are already aware of it. We assure the hon. Member that we are going to strengthen this system and introduce, even at that stage, some sort of accountability so that there may be no under-estimation of costs at the inception stage. We have noted that and we will see that something is done.